MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is okay. . ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Let the Government react. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is for the Government. ...(*Interruptions*)... Now, if the Government can... ...(*Interruptions*)... Okay. Shri Harivansh. ...(*Interruptions*)... All right. You have made your point. Please sit down. ...(*Interruptions*)... No, it is up to the Government. ...(*Interruptions*)... I cannot ask. Please sit down. ...(*Interruptions*)... I have no problem, if the Government wants to... ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, let the Government react. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Harivansh. ...(*Interruptions*)... It is okay. Please. ...(*Interruptions*)... Sit down, please. ...(*Interruptions*)... ठीक है, मैं क्या करूं? **...(व्यवधान)...** आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** It is up to the Government, not for me.

SHRI KIRANMAY NANDA (Uttar Pradesh): Sir, this is the privilege of the Member. The Member has mentioned something. ...(*Interruptions*)... The Minister is here. ...(*Interruptions*)... This is the privilege of the Member to know the reaction of the Minister ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why, I allowed you. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Harivansh.

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, you can always ask the Government to react. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Harivansh.

Alleged conversion of black money into legal money by Shell companies

श्री हरिवंश (बिहार): उपसभापति जी, इस देश में पिछले कुछ दशकों से अमीर व्यवसायी कॉरपोरेट दुनिया के अधिकतर लोगों की दिन दूनी रात चौगुनी सम्पत्ति बढ़ने का रहस्य क्या है, धीरे-धीरे इस देश का सामान्य आदमी यह जानने लगा है। पिछले कुछेक महीनों से, खास तौर से Demonetization के बाद पहली बार हमने कम से कम शैल कम्पनी का नाम सुना। कंफ्यूजन हुआ। बचपन में बर्मा सेल कम्पनी का नाम सुना था। पर Shell कम्पनी का क्या रहस्य है, यह पता किया। शैल कम्पनी यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई काम-धाम, व्यापार फिजिकल बिजनेस नहीं। इनका काम पता चला कि सिर्फ दूसरी बड़ी कम्पनियों, उद्योग संस्थानों के लिए लेन-देन का काम करना। उस रूप में Stock Exchange में listed हैं, कानूनन ठीक भी हैं, पर इनमें से ज्यादातर, 90 फीसदी ऐसी कंपनियां illegal काम में लगी हुई हैं। वह काम कैसा है? गैर-कानूनी काम का माध्यम हैं, ये कंपनियां vehicle for illegal activities, यानी tax avoidance, black को white करना, bankruptcy frauds, fake services schemes, market manipulation और money laundering का काम करना एक भी production का काम ये shell कम्पनियां नहीं

करतीं। tax haven देशों में इनकी जड़ें हैं। मैंने यह क्यों जानना चाहा? 2 मार्च को मैंने *The Times of India* में खबर पढ़ी, 'I-T survey on 12 shell firms reveals ₹ 65 crore black money.' *The Hindu* में 17 मार्च को मैंने खबर पढ़ी, "CAG pulls up I-T Department on shell companies." महाराष्ट्र के Sales Tax Department के ऑडिट में कैग ने पाया कि स्टेट गवर्नमेंट की website पर 2,059 संदिग्ध डीलर्स हैं, जिन्होंने 10,640 करोड़ से अधिक का टैक्स चुराया है, यह CAG Report में है। इसके अतिरिक्त उसमें और भी गंभीर चीज़ें हैं। तीसरी खबर मैंने पढ़ी कि at least, ₹ 3,900 crore was laundered through shell companies between November and December after the ban on high-value banknotes. Investigation by a Central Agency, the Serious Fraud Investigation Office (SFIO), have found it. चौथी खबर मैंने पढ़ी कि कोलकाता में सबसे अधिक 3,000 से अधिक shell कम्पनियां active हैं।

सर, सरकार से मेरा आग्रह है कि ये कम्पनियां कैसे वर्षों से चलती रहीं, जबकि आपके यहां Income Tax Department है, आपके यहां आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन है, ED है? इन सबके बावजूद कैसे यह सब होता रहा? पता चला है कि भारत में 7 लाख shell कम्पनियां हैं, देश में 15 लाख रजिस्ट्रड कम्पनियां हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लाख annual tax देती हैं। सर, मैंने 20 तारीख को Mint में बड़ी खबर पढ़ी कि बेंगलुरु में साढ़े चार एकड़ में एक बड़ा घर बन रहा है, 20 मिलियन डॉलर में penthouse बन रहा है, 40,000 sq. ft. में जिसमें helipad भी होगा। जिस व्यक्ति का यह घर है, वे देश से भागे हुए हैं, उन पर स्टेट बैंक का 6,203 करोड़ का लोन है, interest को मिलाकर 9,000 करोड़ का लोन है। यह जो घर बन रहा है, जिस पर helipad बन रहा है, उसका shell कम्पनियों से क्या रिश्ता है, कम से कम यह सरकार बताए और इस तरह की कम्पनियां अब तक कैसे चलती रहीं, यह देश को बताए।

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI D. P. TRIPATHI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI KIRANMAY NANDA (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्री शरद यादव (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री तपन कुमार सेन: हमारे समाज में जो गंदगी फैली हुई है **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... All are shouting. ...(*Interruptions*)... What is the advantage? ...(*Interruptions*)... I don't hear anything. ...(*Interruptions*)...

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): सर, एक सेल कम्पनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर की कम्पनी है, उसको तो सरकार बेचना चाहती है **...(व्यवधान)...** और यह जो कम्पनी है, उसको बढ़ावा दे रही है। सेल कम्पनी को सेल पर चढ़ा रही है, जो पब्लिक सेक्टर की कम्पनी है। **...(व्यवधान)....**

श्री उपसभापति: अली अनवर अंसारी जी, आप अपने Zero Hour Mention पर बोलिए।

Need for a Central Legislation for protection of street hawkers

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): शुक्रिया महोदय, पिछली सरकार के समय में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए, उन्हें regulate करने के लिए एक कानून बना था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबसे कमज़ोर और निरीह लोगों के लिए यह कानून था, लेकिन उस कानून को cold storage में डाल दिया गया है और जिस तरह से पहले इन रेहड़ी-पटरी वालों से हफ्ता वसूली होती थी, उन पर गुंडा टैक्स लगता था, यह हफ्ता वसूली क्या है — निगम वाले, corporation वाले, municipality वाले इनसे पैसा वसूलते हैं और जो गुंडा टैक्स है, वह लोकल गुंडे उनसे वसूलते हैं। पुलिस भी उन्हें डंडे मारती है, हल्ला गाड़ी लेकर आती है और पुलिस भी हफ्ता वसूली करती है। इनकी संख्या कोई कम नहीं है। सरकार को सबसे पहले सर्वे कराना था कि इस मुल्क में कितने रेहड़ी-पटरी वाले लोग हैं, उनका सर्वे का काम नहीं हुआ। एक rough estimate के अनुसार पचास लाख लोग ऐसे हैं, यानी पचास लाख families इस धंधे में लगी हुई हैं। ये इतने निरीह लोग हैं, जो सड़कों के किनारे और जहां पर कूड़ा पड़ा रहता है, वहां बैठकर अपना रोज़गार सृजित करते हैं। धूप हो, वर्षा हो या ठंड हो, उसमें खड़े रहते हैं। सर, ये लोग जलेबियां बनाते हैं और फल-फूल व सब्जी बेचते हैं। सर, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें ताजी सब्जी मिले, नजदीक में मिले और जलेबियां किसे पसंद नहीं है? सब लोग गरमा-गरम जलेबी चाहते हैं, लेकिन जब इन्हें गुंडे मारते हैं, पुलिस पीटती है, Corporation वाला हफ्ता वसूली करता है, तो कोई इन की मदद के लिए नहीं आता है। सर, इनकी सुरक्षा के लिए यह कानून